International Journal of Financial Management and Economics

P-ISSN: 2617-9210
E-ISSN: 2617-9229
IJFME 2023; 6(1): 104-109
www.theeconomicsjournal.com
Received: 21-12-2022
Accepted: 24-01-2023

बिनोद कुमार
पीएचडी शोधकर्ता,
स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र
विभाग, टी. एम. भागलपुर
विश्वविद्यालय, बिहार, भारत

Corresponding Author:
बिनोद कुमार
पीएचडी शोधकर्ता,
स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र
विभाग, टी. एम. भागलपुर
विश्वविद्यालय, बिहार, भारत

भारत में गरीबी उन्मूलन में कृषि सहकारी समितियों की भूमिका पर एक अनुभवजन्य अध्ययन

बिनोद कुमार

DOI: https://doi.org/10.33545/26179210.2023.v6.i1.178

सारांश
सहकारिता उत्पादक-स्वामित्व और नियंत्रित संगठनों को संदर्भित करती है जो बाजार की विफलता को ठीक करके किसानों की आजीविका में सुधार करते हैं। नीति निर्माता सहकारी समितियों को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए गरीब किसानों की गरीबी उन्मूलन के लिए एक उपयुक्त विकास दृष्टिकोण के रूप में मानते हैं; इसलिए, भारत सरकार इस क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों का निवेश कर रही है, इसे गरीबी कम करने की रणनीति के हिस्से के रूप में प्राथमिकता दे रही है।
कृषि सहकारी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं जो आजीविका विकसित करने और गरीबी को कम करने में सहायक हैं। सहकारिता के ऐसे हिस्सों की स्वीकृति में, अनुकूल क्षेत्र विकास को आगे बढ़ाने में चल रहे वर्षों के लिए एक बहाल उत्साह का प्रदर्शन किया। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को किसानों के लिए कृषि ऋण प्रदान करने, बीज, खाद, कीटनाशक, खेती के उपकरण और हार्डवेयर जैसे बुनियादी कृषि इनपुट स्रोतों को प्रसारित करने, कृषि उपज विपणन सुविधाएं देने और मितव्ययिता और बख्शने की प्रवृत्ति सिखाने की दृष्टि से विकसित किया गया था। किसी भी सहकारिता का प्राथमिक कार्य अपने लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो सहकारी समितियों के लिए कोई हिस्सा नहीं है। सहयोग के क्षेत्र में, प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (PACS) आम तौर पर इसी क्षण और मध्यम अवधि के प्रस्ताव देती हैं। चूंकि, पैक्स जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, प्राकृतिक लोगों के साथ संपर्क का समन्वय करते हैं और किसानों की बजटीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। किसानों की स्थायी आजीविका में पैक्स की भूमिका का अध्ययन करने के लिए, सहकारी समितियों के महत्व को समझने के लिए अध्ययन किया गया है। कीवर्ड: प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, आजीविका, कृषि ऋण, महत्व। अंत में, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सदस्यों को सहकारी दिशानिर्देशों को पूरी तरह से समझने और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए सहकारी दृष्टिकोण की क्षमता को समझने में कुछ साल लगेंगे। साथ ही, सरकार की ओर से कृषि के बुनियादी ढांचे और उद्योग को विकसित करने और छोटे किसानों की गरीबी को कम करने के लिए एक सहकारी नीति को लागू करने के गंभीर प्रयास होने चाहिए।

कुटशब्द: सहकारिता, नीति निर्माता, आर्थिक संसाधन, गरीबी उन्मूलन

प्रस्तावना
भारत, एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, जहां दुनिया के सबसे बड़े सहकारी आंदोलन की नींव रखी गई। डेयरी, चीनी मिलें, कताई मिलें और कृषि में अन्य सहकारी उद्यम उन किसानों के संयुक्त संसाधनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं जो अपनी उपज को

संसाधित करना चाहते हैं। देश में 1,94,195 सहकारी डेयरी समितियां और 330 सहकारी चीनी मिलें संचालित हैं। सहकारी चीनी मिलें देश में उत्पादित चीनी का 35% हिस्सा बनाती हैं। बैंकिंग और वित्त में, सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फैली हुई हैं। स्थानीय स्तर पर ऋण प्रवाह का स्पष्ट उदाहरण ग्रामीण स्तर पर किसान संघों द्वारा स्थापित प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) हैं। ग्राहक सहकारी समितियाँ भारत में कई प्रकार की सहकारी समितियों में से एक हैं जो वस्तुओं को सस्ता बनाकर सभी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का काम करती हैं। ये सहकारी समितियाँ जिनमें केन्द्रीय भंडार, अपना बाजार और सहकारी भंडार प्रमुख उदाहरण हैं। उत्पादकों से सीधे माल खरीदें, इस प्रकार बिचौलियों को हटा दें। यह उपभोक्ताओं को कम कीमत पर आइटम वितरित करेगा।

सहकारिता का इतिहास

18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में सहकारिता की शुरुआत हुई। पिछले 200 वर्षों में, विकसित देशों में सहकारी समितियों ने सफलता और असफलता दोनों का अनुभव किया है। उत्पादक सहकारी समितियाँ जो आज विकसित देशों में मौजूद हैं, वे हैं जो सदस्य आय लाभ के मामले में सफल रही हैं। विशेष रूप से, विकसित देशों में सहकारी समितियाँ सभी आकार के उत्पादकों को एक सहकारी के माध्यम से कम इनपुट कीमतों और उच्च आउटपुट कीमतों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं जो इनपुट उत्पादकों और आउटपुट खरीदारों के साथ सौदेबाजी कर सकती हैं।

स्थानीय कृषि सहकारी समितियों के लिए खाद्य मूल्य श्रृंखला के सभी स्तरों पर काम करना आम बात है। वे स्तर इनपुट आपूर्ति, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन हैं (ओ'ब्रायन, डीजे, और कुक, 2016; ओ'ब्रायन एट अल, 2013; बिर्चेल 2004)। सहकारी समूह के आकार के कारण सामूहिक कार्रवाई के लाभों का उपयोग कर सकते हैं, जबकि समूह के भीतर घनिष्ठ संबंध उन्हें अपने सामूहिक लक्ष्यों की ओर इंगित करने के लिए एक स्व-निगरानी उपकरण प्रदान करते हैं।

साहित्य समीक्षा

स्टैट्ज़ (1987) इंगित करता है कि विशिष्ट संपत्ति किसानों के पास उत्पादन के लिए होती है जैसे कि भूमि, घरेलू श्रम, खेती का अनुभव, आदि, कृषि क्षेत्र में उच्च जोखिम के साथ संयुक्त रूप से किसानों को कम लेनदेन लागत के लिए सामूहिक कार्रवाई में शामिल होने की संभावना है। सामूहिक कार्रवाई व्यक्तिगत किसानों के लिए लेन-देन की लागत को कम करती है क्योंकि प्रत्येक किसान को अब जानकारी खोजने, सौदेबाजी करने और समझौते को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब जानकारी ज्ञात हो जाती है और प्रवर्तन सुनिश्चित हो जाता है, तो सभी सदस्यों की उस तक पहुंच होती है। इस प्रकार, सामूहिक कार्रवाई से छोटे धारकों की लेन-देन लागत कम हो जाती है और इस तरह उनकी शुद्ध कीमत बढ़ जाती है।

अग्रवाल, (2001) प्रोत्साहनों के अलावा, सामूहिक कार्रवाई संसाधन की प्रकृति, सामुदायिक विशेषताओं, समुदाय और संसाधन के बीच अंतर्संबंध, बाजार पहुंच और बाहरी एजेंसियों से प्रभावित हो सकती है।

हिल (2005), युगांडा में छोटे कॉफी उत्पादकों के विपणन व्यवहार के एक सर्वेक्षण में, जिनके पास औसतन 0.20 हेक्टेयर भूमि है, ने पाया कि छोटे कॉफी उत्पादक कम मात्रा और परिवहन लागत के कारण अपने उत्पाद को फार्म गेट पर बेचते हैं।

इथियोपिया में बर्नार्ड और स्पीलमैन (2009) ने पाया कि 1.22 और 4 हेक्टेयर के बीच भूमि वाले मध्यम आकार के किसानों के पास सहकारी समितियों में शामिल होने के लिए पर्याप्त मात्रा और आय है। लेखकों का सुझाव है कि मध्यम आकार के किसानों को सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तावित पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ होता है। उनके उत्पाद के व्यक्तिगत रूप से विपणन की लागत में विपणन जानकारी प्राप्त करना, खरीदारों के साथ सौदेबाजी करना, उत्पाद को स्थानांतरित करना और गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करना आदि शामिल हैं।

भारद्वाज, (2009) विश्व बैंक ग्रामीण विकास और किरायेदार और कृषि-आधारित परिवारों के रूप में अधिकांश गरीबों का विश्लेषण करता है। इस प्रकार, गरीबी में कमी के रूप में ग्रामीण किसान और श्रम के उत्थान का अवलोकन करें। गरीबी में कमी का अर्थ हस्तांतरणीयता के क्षेत्र को मजबूत करना भी है। संपत्ति की पहचान करना, उपलब्ध संपत्ति तक पहुंच बनाना और कमांड कल्याण के लिए इसकी हस्तांतरणीयता को बढ़ाना गरीबी में कमी के मूल तत्व हैं। गरीबी एक बहुआयामी अवधारणा है।

फिशर और कैम (2011) केन्या में 444 केला उत्पादकों के एक क्रॉस-अनुभागीय सर्वेक्षण का उपयोग करते हैं ताकि प्रभावित कारकों का आकलन किया जा सके कि वे उत्पादक संगठनों में शामिल होते हैं या नहीं। सर्वेक्षण किए गए उत्पादकों के पास औसतन 1.3 हेक्टेयर भूमि है और उन्हें छोटे पैमाने पर उत्पादक

माना जाता है। किसान घरेलू खपत और घरेलू बाजार दोनों के लिए केले उगाते हैं। उनके निष्कर्ष बताते हैं कि बड़े किसानों (4 हेक्टेयर से अधिक भूमि) के पास स्वतंत्र रूप से खेती करने के लिए पर्याप्त संपत्ति और पैसा है।

इलियोपोलोस और कुक (2013) का तर्क है कि सहकारी समितियों को अपने संचालन में चार अतिरिक्त सामूहिक कार्रवाई समस्याओं का सामना करना पड़ता है: क्षितिज, पोर्टफोलियो, नियंत्रण और प्रभाव। समय क्षितिज की समस्या तब होती है जब सदस्यों को सहकारी के विकास में निवेश करने के लिए निरुत्साहित किया जाता है क्योंकि निवेश द्वारा उत्पन्न आय पर सदस्य का दावा उस परिसंपत्ति के उत्पादक जीवन से कम होता है।

खातीवाड़ा (2014) का तर्क है कि सहकारी समितियों में भारी निवेश के बावजूद सहकारी समितियों के खराब प्रबंधन के कारण छोटे किसानों की आय बढ़ाने के मामले में सहकारी समितियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। सहकारी समितियां प्रबंधन की कमी और उपयोगकर्ताओं के बीच उद्यमशीलता कौशल की कमी से ग्रस्त हैं, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मानव संसाधन का विकास एक महत्वपूर्ण कारक है।

अनुसंधान उद्देश्य

यह अध्ययन छोटे किसानों की आय और गरीबी पर कृषि सहकारी समितियों के प्रभाव का आकलन करता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारत में अधिकांश किसान छोटे किसान हैं, जो मुख्य रूप से निर्वाह कृषि में शामिल हैं।

अनुसंधान पद्धति

पेपर समीक्षा किए गए शोध का सरल वर्णनात्मक लेआउट है। मानव विकास सूचकांक सूचक उपलब्ध है और सहकारी समितियों पर डेटा का विश्लेषण किया गया है।

वर्तमान परिदृश्य - शक्ति, कमजोरियां, अवसर और खतरा का विश्लेषण

भारत की सहकारी समितियों का मध्यम इतिहास रहा है, हालांकि सहकारी संस्कृति पहले शुरू हो चुकी है। भारत की सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण और सार्वजनिक रूप से समुदाय आधारित संस्थानों के रूप में पहचाना गया है। इस संबंध में यहां हम भारत में सहकारिता का सरल शक्ति, कमजोरियां, अवसर और खतरा का विश्लेषण करेंगे।

शक्तिः सहकारिता गृहस्थी का निकटतम वित्तीय, सहायता केन्द्र एवं सुलभ फर्म है। सेवा तक पहुंच, अधिकारिता और समुदाय के सदस्यों की सौदेबाजी की क्षमता में अचानक वृद्धि हुई है। सहकारिता को अब गरीबी कम करने और सामाजिक-आर्थिक प्रगति के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में पहचाना गया है।

कमजोरियां: सदस्यों के बीच सहकारिता के सिद्धांत और मूल्यों के बारे में जागरूकता और ज्ञान बहुत कमजोर है। सहकारी समितियों के तहत बढ़ते अनैतिक वित्तीय लेन-देन संवार रहे हैं। इसके अलावा, सहकारिता विभाग और उसके कार्यालयों की संस्थागत क्षमता।

सहकारी समितियों की बढ़ती संख्या कुछ समस्याएं हैं। सहकारिता नैतिक भागीदारी चाहती है, और इसे पर्यावरण के भीतर और अंतःक्रिया में बनाए रखने के लिए चुनौती दी गई है।

अवसर: सहकारिता संभावित रूप से सशक्त कर सकती है, गरीबों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। वितरणात्मक न्याय के साथ सामाजिक-आर्थिक प्रगति सबसे बड़ा अवसर है जो सहकारिता उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा, यह ग्रामीण और सीमांत गरीबों को बांधता है और सौदेबाजी करने, लाभ प्राप्त करने और उनकी सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थागत मंच प्रदान करता है। शहरी मध्यम वर्ग के पास सेवाओं और पूंजी तक पहुंच हो सकती है और वे अपनी उद्यमी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ग्रामीण लोग सेवा तक पहुंच और साथ ही उद्यम विकास के लिए पूंजी तक पहुंच से बेहतर लाभ उठा सकते हैं। सहकारी ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण लोगों के लिए निकटतम और सबसे आसान वित्तीय लेनदेन / सेवा प्रदाता के रूप में काम कर रहा है।

खतरा: सहकारिताएं इन दिनों निजी व्यवसाय हो रही हैं। हालांकि इसे सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है और वास्तविक सहकारी समितियों को हतोत्साहित नहीं कर रहा है, लेकिन वृद्धि की दर बढ़ रही है। अवैध वित्तीय लाभ में खामियों को दूर करने के लिए सहकारी समिति और आम लोगों के डोमेन को प्रदूषित करना। कमजोर निगरानी के साथ-साथ कमजोर कानूनी प्रावधान ने जनता के पैसे को कमजोर क्षेत्र में धकेल दिया है। सबसे पहले, और तथ्यात्मक रूप से, कोई नहीं जानता कि काठमांडू में सहकारी संस्था कैसे काम कर रही है। एक सामाजिक और सदस्य-आधारित

व्यवसाय के रूप में सहकारिता के लिए राज्य द्वारा प्रयोग किए गए लाभ का उपयोग व्यक्ति के हित को पूरा करने के लिए किया गया है। जैसा कि सहकारिता को अभी तक स्पष्ट रूप से वित्तीय गतिशीलता के लिए पहचाना नहीं गया है, लेन-देन और आर्थिक मूल्य अभी तक अच्छी तरह से हिसाब नहीं किया गया है। सहकारिता के पतन के खतरे को एक बार फिर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

गरीबी उन्मूलन में सहकारी भूमिका

मूल रूप से, गरीबों के पास कमजोर रूप से हस्तांतरणीय संपत्ति होती है, या तो उनकी पहुंच के अभाव में या उनके पास मौजूद संपत्ति की मान्यता के अभाव में। गरीबों में कल्याण का अभाव है। गरीबी की सापेक्ष अवधारणा लोगों, घर या ऐसे अन्य पहलुओं के बीच कल्याण के अंतराल पर ध्यान केंद्रित करती है। सहकारिता कई तरीकों से गरीबी कम करने में योगदान देती है। सहकारिता के ये प्रमुख क्षेत्र जो गरीबी कम करने में योगदान करते हैं वे हैं:

संपत्ति में वृद्धि: ग्रामीण गरीबों और शहरी गरीबों की संपत्ति अलग-अलग होती है। सहकारिता गरीब परिवार की स्थानीय संपत्ति को मात्रात्मक और गुणात्मक संगठन में सक्षम बनाती है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम के लिए उत्पादन प्रबंधन और पूंजी दोनों का अभाव है। शहरी क्षेत्रों में विविध उद्यम और विचार हैं। उनके पास पूंजी और वितरण चैनलों की कमी है। सहकारी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी अंतर आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है और संपत्ति को बढ़ाने में मदद करता है।

पहुँच बढ़ाएँ: पूँजी, बाज़ार और गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं तक पहुँच इन दिनों सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सहकारिता इन पहलुओं तक पहुंच बनाने के लिए संस्थागत व्यवस्था है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों और दूध की मात्रा बनाने में मदद करते हैं और शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के वितरण में सहायता करते हैं। वे दैनिक बचत और निवेश के माध्यम से पूंजी तक पहुंच प्रदान करते हैं।

हस्तांतरणीयता के डोमेन को मजबूत करना: हस्तांतरणीयता के डोमेन से तात्पर्य आवश्यक कल्याण को आदेश देने के लिए संपत्ति को स्थानांतरित करना है। सहकारी संपत्ति के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाता है और फिर बाजार प्रदान करता है। विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बाजार में आसानी से बिक जाते हैं। एक सदस्य आधारित और समुदाय आधारित व्यवसाय होने के नाते, इसकी सामाजिक पूंजी और विश्वास उत्पाद को लाभ में बदलने का काम करता है। व्यावसायिक अधिकारों पर लाभ और समानता का समान वितरण भी निर्णय लेने का समर्थन करता है ताकि निर्माता या सेवा निर्माता के वांछित पहलू परिलक्षित हों।

वेलफेयर कमांडिंग: सेवा, नकद या पहुंच के रूप में लाभ कल्याण सृजन में परिवर्तित हो जाते हैं। परिवार की आय, सामाजिक स्थिति और क्षमता में वृद्धि हुई है। इससे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अवसरों को ग्रहण करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। यह समुदाय के परिवारों को समृद्धि के प्रगतिशील चक्र में लाता है। उदाहरण के लिए: किसान के पास ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ गाय/भैंस हैं और कम संख्या में सब्जियां पैदा करता है। व्यक्तिगत परिवहन लागत अधिक है। सहकारी समितियां इस छोटी राशि को एकत्र करती हैं और इन सामानों को बाजार तक आसानी से पहुंचाती हैं। लाभों का बंटवारा समान रूप से प्रबंधित किया जाता है।

सहकारी समितियों के माध्यम से गरीबी में कमी की रणनीतियाँ

सहकारी अनिश्चित काल के लिए कई तरह से पीआर का समर्थन कर सकता है। लेकिन योगदान और मूल्य जोड़ने के विचारों का अनुकूलन अधिक महत्वपूर्ण है। अब्रीशम आरिफ गरीबी कम करने में सहकारी भूमिका पर लोगों की नकारात्मक धारणा की पहचान करता है। यह पाया गया कि ग्रामीण लोगों के नकारात्मक विचारों के लिए कमजोर क्षमता, संसाधनों की कमी और भागीदारी प्रमुख कारक थे।

समुदाय आधारित दृष्टिकोण: एक सदस्य केंद्रित समुदाय आधारित उद्यम के रूप में सहकारिता को सहायता, बढ़ावा देना और प्रेरित करना। सामुदायिक विकास को दो पहलुओं से प्रेरित किया जा सकता है। सबसे पहले, यह स्थानीयकरण उत्पन्न करता है, समुदाय में अवसरों और आय का आयात करता है। दूसरा, यह समान वितरण में मदद करता है और खपत और निवेश क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।

आर्थिक दृष्टिकोण: सहकारिता मिश्रित आर्थिक दृष्टिकोण है इस प्रकार राष्ट्रीय आर्थिक उत्थान के लिए एक उपयुक्त विचार के रूप में पहचान की जाती है। समुदाय आधारित व्यवसाय न तो निजी होते हैं और न ही सार्वजनिक। समुदाय विकास की नींव है।

संस्थागत दृष्टिकोण: सामुदायिक व्यवसाय के आधार पर एक अच्छी शासी संस्था के रूप में सहकारी समिति का विकास संभावित रूप से समुदाय को गरीबी से लड़ने और खतरों से बचाव के लिए स्थानीय ताकत को एकत्रित करने में योगदान देगा। सहकारिता एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जो शेयरहोल्डिंग को छोड़कर समान प्रतिनिधि अधिकार उत्पन्न करती है। लाभ स्वामित्व और लेन-देन दोनों के आधार पर समान रूप से साझा किए जाते हैं। यह आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था उत्पन्न करने का एक एकीकृत तंत्र भी है।

नीतिगत बुनियादी ढाँचा: "हमें भारत में सहकारिता की स्थिति को कैसे देखना चाहिए?" नीतिगत बुनियादी ढांचे की कमी ने सहकारी समितियों पर एक विविध और परस्पर विरोधी दृष्टिकोण पैदा किया है। इसने सहकारी समितियों की भूमिका को छायांकित किया है और भारत में मूल्य और कुशल सहकारी आंदोलन के फलने-फूलने में बाधा उत्पन्न की है। सहकारी अधिनियम, 1991 और विनियमन उभरती हुई सहकारी समितियों से निपटने के लिए अपर्याप्त रूप से परिपक्व हैं। अक्सर यह महसूस किया जाता है कि नैतिक तरीके से चुनौतियों की संख्या के साथ बड़ी संख्या में सहकारी समितियों का प्रबंधन करना पर्याप्त नहीं है। अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने का अर्थ है निष्पक्ष खेल के लिए आधार प्रदान करना।

मूल्य और सिद्धांत के प्रति सहकारी समितियों को जगाना और प्रेरित करना: "अपेक्षित सहकारिता" के लिए दीर्घकालिक समाधान सहकारी सिद्धांत के प्रति जागरूकता, सशक्तिकरण और प्रेरणा है। जब तक हम यह प्रदर्शित नहीं करते कि "सहकारिता सिद्धांत के भीतर सफल हो सकती है" और सहकारिता के बीच सहकारिता के मूल्य और सिद्धांत को स्वीकार करने और उचित सम्मान के साथ मानदंडों को आत्मसात करने के लिए विश्वास पैदा करते हैं; हम बेहतर सहकारी आंदोलन शुरू नहीं कर सकते। वास्तव में, यह आरंभ करने की सबसे गंभीर रणनीति में से एक है। यह सच है कि अच्छी तरह से विनियमित सहकारिता ही गरीबी कम करने में सकारात्मक योगदान दे सकती है।

ग्रामीण सहकारी समितियों को मजबूत करना: ग्रामीण सहकारी समितियाँ न केवल एक सामुदायिक व्यवसाय हैं बल्कि एक भरोसेमंद वित्तीय भागीदार भी हैं, सामाजिक परिवर्तन पर चर्चा करने और निर्देशात्मक लोकतंत्र का अभ्यास करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था है। इन समुदाय-आधारित संस्थाओं को आवश्यक समर्थन के साथ सशक्त और मजबूत किया जाना चाहिए। इस प्रकार, सहकारी सशक्तिकरण रणनीतियों को इन पहलुओं में अच्छी तरह शामिल किया जाना चाहिए। यह गरीबी में कमी के पहलुओं को सक्रिय करता है।

निष्कर्ष

भारत के ग्रामीण संदर्भ में सहकारिता संभावित रूप से गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है। सहकारिता का अर्थ है आय, सामाजिक और धारणा आधारित गरीबी में कमी। आगामी चुनौतियाँ कमजोर निगरानी के साथ कमजोर कानूनी संस्थागत व्यवस्थाओं का परिणाम हैं। सहकारी में एक रुपये का मतलब गरीबी कम करने के नजरिए से वाणिज्यिक बैंक के एक रुपये से अलग है। सरकार को सहकारी समितियों में धन की राशि के बारे में ईमानदार होना चाहिए और साथ ही उन क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद और आसान तरीके से सेवाओं का मूल्य जहां निजी क्षेत्र सहज महसूस नहीं करते हैं। सहकारिता आंदोलन का मतलब गरीबी कम करना भी था। पतन की त्रासदी के तुरंत पहले, यह बेहतर है कि हम सिद्धांत और मानदंडों में सहकारिता का प्रबंधन करें। सहकारिता को गरीबी उन्मूलन क्षेत्र की ओर मोड़ने में यह सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। ग्रामीण भारत में नैतिक और लोकतांत्रिक रूप से संस्थागत सहकारी समितियों से बहुत कुछ उम्मीद की जा सकती है।

सन्दर्भ

1. Asfaw S, Shiferaw B, Simtowe F, Lipper L. Impact of modern agricultural technologies on smallholder welfare: Evidence from Tanzania and Ethiopia. Food policy. 2012;37(3):283-295.
2. Baviskar BS, Attwood DW. Rural co-operatives in India: A comparative analysis of their economic survival and social impact. Contributions to Indian sociology. 1984;18(1):85-107.
3. Central Bureau of Statistics. National Sample Census of Agriculture India 2011/12: National Report. Kathmandu: Central Bureau of Statistics, National Planning Commission, Government of India; c2013.
4. Johnson D. Insights on poverty. Development in Practice. 2010;12(2):127-137.
5. Khan HA. Freedom as Development. USA, 2004, January.
6. Lipton M. Why poor people stay poor. In E. John Harris, Rural development theories of pheasant economy and agrarian change; c1982. p. 67- 80.
7. NPC. The tenth periodic plan: Poverty Reduction strategic paper (2002-07). Kathmandu: National Planning Commission; May, 2003.
8. Pike SJ. Portfolios of the Poor: How the World's Poor Live on $2 a Day. Development in Practice. August

2010;20(6):743-744.
9. Rynell A. Causes of Poverty: Findings from Recent Research. The Heartland Alliance, Mid-America Institute on Poverty. The Heartland Alliance; c2008.
10. Sizya MJ. The role cooperatives play in poverty reduction in Tanzania. Observation report, Cooperative College, Moshi, Tanzania; c2001.
11. Todaro M, Smith S. Poverty. In M. Todaro, & S. Smith, Economic Development. India: Pearson Publication, 2003, Eight Edition ed., p. 263-264.